

संपादकीय

चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने वाले 3 बड़े सुधारः भारत के लोकतंत्र को मिलेगा नया आधार

यह सच है कि भारतविश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ 9.68 करोड़ से अधिक मतदाता संविधान के तहत अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। लेकिन यह व्यापक चुनावी प्रक्रिया समय के साथ कई चुनौतियों से घिर गई है—जिनमें धनबल, अपराधीकरण, फर्जी मतदान, और असमान प्रचार तंत्र प्रमुख हैं। पारदर्शिता की कमी और संस्थागत खामियों में चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अतः यह आवश्यक ही गया है कि कुछ चुनौतियों और व्यापक सुधार किए जाएं, जिससे भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत, भरोसेमंद और प्रतिनिधित्वपूर्ण बन सके। इसी उम्मीदवारों हैं भारत में चुनाव संचालन की वर्तमान व्यवस्था के बारे में। भारत में चुनावों को नियंत्रित करने वाले मुख्य प्रावाहनों शामिल हैं—विधान का अनुच्छेद 324—यह भारत के चुनाव आयोग को देश के चुनावों का संचालन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार देता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951—पहला अधिनियम मतदाता सूची और नियाचन क्षेत्रों की निर्धारण को निर्देशित करता है, जबकि दूसरा चुनावी प्रक्रिया, उम्मीदवारों की योग्यता और चुनाव विवादों का निर्धारण करता है। मतदाता पंजीकरण नियम, 1960—यह नियम मतदाता सूची की शुद्धता और सुधार की प्रक्रिया तय करता है, जिससे मतदाता डेटा की एक सूची बनी रहती है।

परिसीमन अधिनियम, 2002—यह कानून जनसंख्या के अनुसार नियाचन क्षेत्रों की सीमा तय करता है, जिससे जनसंख्याकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। आदर्श आचार सहित—यह एक नैतिक सहिता है, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलोंके आचरण को नियंत्रित करती है।

एरोनेट प्रणाली—चुनाव आयोग की यह डिजिटल व्यवस्था पूरे देश की मतदाता सूची को केंद्रीकृत और मानकीकृत करती है। अब बात करते हैं प्रमुख चुनावी समस्याओं की वाईपीट सत्यापन की सीमाएँ—वर्तमान में केवल पाँच मरीनों का मिलान किया जाता है, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं। मतदाता सूची में विंसंगतियाँ—फर्जी नाम और डिप्लिकेट प्राप्तिक संबंध के चलते मतदाता की शुचिता पर संकट बना रहता है। आदर्श आचार सहितोंका उल्लंघन—स्टार प्राचारोंके द्वारा भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक टिप्पणी बांब-बार देखी जाती हैं, लेकिन कार्रवाई कर महती है। राजनीतिक दलोंका अनियंत्रित खर्च—जहाँ उम्मीदवारोंपर खर्च सीमा तय है, वही दलोंपर प्रभावी सीमा नहीं है। 2024 चुनाव में हीरे 1.35 लाख करोड़ से अधिक खर्च हुआ। राजनीतिक दलोंका अपराधीकरण—2024 में 80% संसदोंपर अपाराधिक मामले दर्ज थे। इससे लोकतंत्रिक वैधानिक वर्षारोही होती है। डिजिटल दुर्घटना और डीपेक्स-फार्मल सीमोंपर फर्जी खर्चोंसे मतदाता अपनी योग्यता को उपराहा किया जाता है। एकाधिक सीमोंसे चुनाव लड़ना—इससे उपचुनावी की आवश्यकता उत्पन्न होती है और सार्वजनिक संसाधनोंकी बढ़ावी होती है। राजनीतिक दलोंमें अंतरिक लोकतंत्र की कमी-पार्टीयोंमें पारदर्शी चुनाव और नेतृत्व की समय-सीमा नहीं होती, जिससे जबाबदेही प्रभावित होती है। तीन प्रमुख सुधार जो लोकतंत्र को देसकते हैं नया आधार—वाईपीट सत्यापन की वैज्ञानिक प्रणाली—वाईपीट मिलान की क्षेत्रीय और नमूना—आधारित बनाना। आवश्यक है यदि किसी क्षेत्रमें इवीएम और वाईपीट में अंतर पाया जाए, तो वहाँ की सभी मरीनों की मैन्युअल गिनती अनिवार्य होनी चाहिए। इससे मतदाता विश्वास बढ़ाता है और तकनीकी भरोसे को बल्मियोगा। राजनीतिक दलोंके चुनावी खर्च पर नियंत्रण—उम्मीदवारोंकी तरह राजनीतिक दलोंके लिए भी खर्च की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। इसके साथ ही आरटी आईके तहत दलोंको लाने से उनके वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' जैसी अवधारणाओंको लागू करने से बार-बार के चुनावोंकी लागत को भी कम किया जा सकता है। अपराधीकरण पर कड़ी कार्रवाई—सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरणके अलावा, उम्मीदवारोंपर मुकदमे लोबिट होनेकी स्थिति में तीजे सेनिर्णयके लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए। जिन पर गंभीर आपोर तय हो जाएं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिये कड़े प्रावधान लागू करनेहोंगे।

अन्य जरूरी सुधारः—टोटलाइजर मरीनोंका प्रयोग: जिससे मतदाता की गोपनीयता बनी रहे और मतदातन केंद्र-वासी धर्मकियोंको रोका जा सके। एपिक नंबर को आधार से जोड़ा: जिससे डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ हाईट जा सकें, लेकिन डेटा सुधार के मजबूत उपयोग के साथ। स्टार प्रचारक का दर्जा रह करना: आदर्श आचार सहितोंका उल्लंघन पर बार-बार के चलते मतदाता की गमनाकरी मिलान की वैज्ञानिक प्रणाली—वाईपीट सत्यापन की क्षेत्रीय और नमूना—आधारित बनाना। आवश्यक है यदि किसी क्षेत्रमें इवीएम और वाईपीट में अंतर पाया जाए, तो वहाँ की सभी मरीनों की मैन्युअल गिनती अनिवार्य होनी चाहिए। इससे मतदाता विश्वास बढ़ाता है और तकनीकी भरोसे को बल्मियोगा। राजनीतिक दलोंके चुनावी खर्च पर नियंत्रण—उम्मीदवारोंकी तरह राजनीतिक दलोंके लिए भी खर्च की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। इसके साथ ही आरटी आईके तहत दलोंको लाने से उनके वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' जैसी अवधारणाओंको लागू करने से बार-बार के चुनावोंकी लागत को भी कम किया जा सकता है। अपराधीकरण पर कड़ी कार्रवाई—सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरणके अलावा, उम्मीदवारोंपर मुकदमे लोबिट होनेकी स्थिति में तीजे सेनिर्णयके लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट लोबिट होने से बार-बार चलते रहे। अंत में कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र तभी सशर्त होता है। इसके लिये केवल चुनाव आयोग को प्राप्तवार्ष घटे और समान अवसर बढ़े। अंत में कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र तभी सशर्त होता है। इसके लिये केवल चुनाव आयोग नहीं, बल्कि न्यायपालिका, राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक समाज—सभी को मिलकर प्रणालीय खामियोंको दूर करने में अपना सक्रिय योगदान देना होगा। तीन सुधार—वाईपीट सत्यापन की पारदर्शिता, दलोंके खर्च पर नियंत्रण, और अपराधीकरण पर कड़ा रुख—अगर इमानदारी से लागू किए जाएं, तो भारत नकेवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे विश्वसनीय लोकतंत्र बन सकता है।

आज का राशिफल

	मेष: आज व्यवसायिक नियंत्रणोंमें सावधानी बरतनी होगी, किसी निवेश में जल्दीजा न करें। अनुभवी लोगोंसे मार्गदर्शन मिल सकता है जो आपको स्थिति सुधार सकती है। पारिवारिक चातावरण को शांत बनाए रखने के लिये क्योंकि ताव की चाता है।
	वृषभ: कार्यक्षेत्र में तकनीकी दिवकरोंके चलते रुकावटें आ सकती हैं। साथेदारी में काम कर रहे जातकोंको लाभ के दंवारे को लेकर चिंता सतायी। नियंत्रण लेने में दुर्दणोंसे की गए से बचें, इससे उलझन बढ़ सकती है। जीवनसारीके साथ समयविताने की इच्छा प्रबल रही है, लेकिन नियाचे साथ वैयाकिं समान बढ़ेगी।
	मिथुन: आज किसी भी लोहे के उपकरण का प्रयोग सावधानी से करें। जीवनसारीकी बातोंको लेकर तीखी बहस संभव है। कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता पर नियंत्रण, जासोन अन्तर्वार्षिक दल: जिससे जनन को जानकारी मिले कि पैसा कहां से आया और कैसे खर्च हुआ। स्वीपी कार्यक्रम का विस्तार: जिसमें काम करने से बार-बार के चुनावोंको नियंत्रित करने की वायदा। और डिजिटल साक्षरता को शामिल किया जाए। आजकीतन अधिनियम के लिए वित्तीय विवादोंकी जारी रहनी चाहिए। इससे लोकतंत्र की असरोंको लेकर चिंता सतायी। नियंत्रण लेने में दुर्दणोंसे की गए से बचें, इससे उलझन बढ़ सकती है। जीवनसारीके साथ वितानोंकी इच्छा प्रबल रही है, लेकिन नियाचे साथ वैयाकिं समान बढ़ेगी।
	कर्क: आज आपको कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा और समान मिलेगा। व्यापार विस्तार की योजना बनाएं, जो भविष्य के लिए लाभदायक दूरवार्षीय खामियोंको लेकर चिंता सतायी। नियंत्रण लेने में दुर्दणोंसे की गए से बचें, परिवारिक सदस्य आपकी बातोंको असरोंसे बचाएं। अंत में कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र तभी सशर्त होता है। इसके लिये केवल चुनाव आयोग को प्राप्तवार्ष घटे और समान अवसर बढ़े। अंत में कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र तभी सशर्त होता है। इसके लिये केवल चुनाव आयोग नहीं, बल्कि न्यायपालिका, राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक समाज—सभी को मिलकर प्रणालीय खामियोंको दूर करने में अपना सक्रिय योगदान देना होगा। तीन सुधार—वाईपीट सत्यापन की क्षेत्रीय और नमूना—आधारित बनाना। आवश्यक है यदि किसी क्षेत्रमें इवीएम और वाईपीट में अंतर पाया जाए, तो वहाँ की सभी मरीनों की मैन्युअल गिनती अनिवार्य होनी चाहिए। इससे मतदाता विश्वास बढ़ाता है और तकनीकी भरोसे को बल्मियोगा। राजनीतिक दलोंके चुनावी खर्च पर नियंत्रण—उम्मीदवारोंकी तरह राजनीतिक दलोंके लिए भी खर्च की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। इसके साथ ही आरटी आईके तहत दलोंको लाने से उनके वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' जैसी अवधारणाओंको लागू करने से बार-बार के चुनावोंकी लागत को भी कम किया जा सकता है। अपराध

